भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5913

उत्तर देने की तारीख-30/03/2026

आंध्र प्रदेश में उन्नत भारत अभियान 2.0

†5913. **श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में उन्नत भारत अभियान (यूबीए) 2.0 के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है और इसमें भाग लेने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों, गोद लिए गए गांवों और शामिल छात्रों का जिला-वार और विशेषकर कोनासीमा जिले के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) आंध्र प्रदेश में, और विशेषकर कोनासीमा जिले के संबंध में यूबीए 2.0 के अंतर्गत सतत कृषि, जल प्रबंधन, स्वच्छता, ग्रामीण ऊर्जा और आजीविका सहित क्षेत्रीय हस्तक्षेपों और प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यूबीए 2.0 के कार्यान्वयन के लिए आंध्र प्रदेश में प्रतिभागी संस्थानों, क्षेत्रीय समन्वय संस्थानों और जिला प्रशासन के बीच समन्वय तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में यूबीए 2.0 के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ.) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण विकास संबंधी परिणामों और छात्र को शामिल किए जाने के संदर्भ में आंध्र प्रदेश में यूबीए 2.0 के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश में और विशेषकर कोनासीमा जिले में यूबीए 2.0 को सुदृढ़ करने और विस्तारित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क): उन्नत भारत अभियान (यूबीए) शिक्षा मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है जिसे सितंबर 2014 में शुरू किया गया था। यह ग्रामीण समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करने के लिए देश में उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई), जिन्हें प्रतिभागी संस्थान (पीआई) भी

कहा जाता है, को गांवों और स्थानीय समुदायों से जोड़ता है। यूबीए का उद्देश्य छात्रों को ग्रामीण समुदायों और अन्य सरकारी संगठनों के करीब लाना है जिसका अंतिम लक्ष्य गांवों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के बारे में छात्रों को संवेदनशील बनाना है। इसने गांवों में काम करने के लिए हितधारकों जैसे एचईआई, सरकारी संगठनों, युवाओं, गैर सरकारी संगठनों आदि का एक विस्तृत नेटवर्क बनाया है। यह योजना उच्चतर शिक्षा संस्थानों के छात्रों को गांवों के सामने आने वाली समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है और उन्हें इन समस्याओं के व्यवहार्य समाधान विकसित करने के लिए गांवों के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

यूबीए के तहत, 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 22,000 से अधिक गांवों को शामिल करते हुए 4,806 से अधिक पीआई का एक नेटवर्क नामांकित किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली इस कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय समन्वय संस्थान (एनसीआई) के रूप में कार्य करता है। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, देश भर में 50 क्षेत्रीय समन्वय संस्थानों (आरसीआई) को नामित किया गया है और डोमेन-विशिष्ट प्रौद्योगिकीय समाधान प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों द्वारा समन्वित 15 विषय विशेषज्ञ समूहों (एसईजी) का गठन किया गया है।

आंध्र प्रदेश में 428 उच्च शिक्षा संस्थान (एचईआई) यूबीए के तहत पीआई (भागीदार संस्थान) के रूप में नामांकित हैं और छात्रों तथा शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी के साथ 2030 गांवों में काम कर रहे हैं। इसके अलावा, कोनासीमा जिले में 12 पीआई हैं जो यूबीए गतिविधियों में लगे हुए हैं और 60 गांवों में काम कर रहे हैं। इन संस्थानों को क्षेत्रीय समन्वय संस्थानों अर्थात - आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम और श्री वेंकटेश्वर पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय (एसवीवीयू), तिरुपति द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है। इन संस्थानों में यूबीए गतिविधियों में हजारों छात्र शामिल हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में 428 पीआई में से प्रत्येक को गांव का अध्ययन करने और संबंधित गतिविधियां चलाने के लिए 50,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान स्वीकृत और जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश में पीआई की विस्तृत सूची यूबीए पोर्टल पर उपलब्ध है: https://unnatbharatabhiyan.gov.in/list-participating-institutes?csrf_यूबीए=594d8e100b4e321d7aeb4a452dde65dd&aishe_code=&institute_id=&state_id=2&district_id=&submitSearch=

(ख): यूबीए 2.0 के तहत, आंध्र प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में 24 क्षेत्रीय हस्तक्षेपों और प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों को मंज़ूरी दी गई है, जिनमें सतत कृषि, जल प्रबंधन, स्वच्छता, ग्रामीण ऊर्जा और आजीविका शामिल हैं।

(ग): आंध्र प्रदेश में उन्नत भारत अभियान (यूबीए) 2.0 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, इसमें भाग लेने वाले संस्थानों (पीआई), क्षेत्रीय समन्वय संस्थानों (आरसीआई) और ज़िला प्रशासन के बीच एक सुव्यवस्थित समन्वय तंत्र मौजूद है। आरसीआई और पीआई के बीच यह समन्वय यूबीए नेटवर्क के अंतर्गत आने वाले गाँवों में की जाने वाली गतिविधियों की उचित योजना

बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने, उनकी निगरानी करने और उनका मूल्यांकन करना सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही, सरकारी योजनाओं के साथ सामंजस्य और प्रशासनिक सहायता प्रदान करने में ज़िला प्रशासन भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(घ): पिछले तीन वर्षों के दौरान, आंध्र प्रदेश में यूबीए योजना के तहत कुल 91.63 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। इस राशि में आरसीआई को 16.63 लाख रुपये, पीआई को 66.50 लाख रुपये और प्रौद्योगिकी उपायों के लिए स्वीकृत 8.50 लाख रुपये शामिल हैं।

(ङ): सरकार ने स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा आवधिक राष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकनों के माध्यम से यूबीए की प्रगति और प्रभावकारिता का आकलन किया है। इस योजना का मूल्यांकन सबसे पहले वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान द्वारा किया गया था। इसका पुनर्मूल्यांकन भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा वर्ष 2025-26 में किया गया है। इन मूल्यांकनों में आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों को शामिल किया गया और यह निष्कर्ष निकाला गया कि यूबीए एक अत्यधिक प्रासंगिक और प्रभावी कार्यक्रम है, जो जमीनी स्तर के ग्रामीण विकास के साथ शैक्षणिक उद्देश्यों का अनूठा संयोजन करता है। इन मूल्यांकनों में यह निष्कर्ष भी निकाला गया है कि इस योजना ने सहभागी शासन, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामाजिक नवाचार के लिए एक सुदृढ़ आधार तैयार किया है।

(च): सरकार ने पूरे देश में, जिसमें आंध्र प्रदेश राज्य और कोनासीमा ज़िला भी शामिल हैं, यूबीए 2.0 को मज़बूत करने और उसका विस्तार करने के लिए कई कदम उठाए हैं। आईआईटी दिल्ली यूबीए का राष्ट्रीय समन्वय संस्थान (एनसीआई) है, जो 50 आरसीआई के साथ मिलकर इस योजना के ज़मीनी स्तर पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है; ये आरसीआई उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के क्षेत्र-विशेष प्रबंधन को सुनिश्चित करते हैं। इस योजना को आरसीआई और एसईजी द्वारा, राज्य सरकारों, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के समन्वय से सहायता प्राप्त है, ताकि इसकी निगरानी को मज़बूत किया जा सके और इसका विस्तार अधिक ग्रामीण समूहों तक किया जा सके।

ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वह ज़िला कलेक्टरों/ज़िला मजिस्ट्रेटों/ज़िलों के अन्य संबंधित अधिकारियों के माध्यम से यूबीए योजना के साथ सहयोग करे। इस कार्यक्रम को और अधिक ग्रामीण समूहों तक पहुँचाने के लिए, सरकार राज्य सरकारों, ज़िला प्रशासनों और संबंधित मंत्रालयों के साथ नियमित रूप से संवाद करके इस योजना को बढ़ावा दे रही है, ताकि यूबीए के तहत कार्यरत संस्थानों को पर्याप्त सहयोग प्रदान किया जा सके।

*****